

**P.C.O. at Kuttiyadi (Kerala)**

**1797. Shri Pottekkatt:**  
**Shri A. V. Raghavan:**  
**Shri Mohammed Koya:**

Will the Minister of Communications be pleased to state:

(a) the progress made in the matter of providing a Public Call Office at Kuttiyadi Post Office in the Badagara Taluk of Kerala; and

(b) when the P.C.O. will be opened?

**The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri Jaganatha Rao):** (a) The required quantity of copper wire has just been arranged on priority. The work will be commenced in August, 1966.

(b) The P.C.O. is expected to be opened by October, 1966.

**Super-Phosphate Factory**

**1798. Shri V. V. Thevar:** Will the Minister of Petroleum & Chemicals be pleased to state:

(a) whether it is proposed to establish a Super-phosphate Factory in Thanjavur, Madras State;

(b) if so, whether it will be in the private sector or public sector; and

(c) when it will start production?

**The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri Alagesan):** (a) No proposal to set up a Superphosphate factory at Thanjavur has been received by Government.

(b) and (c) Do not arise.

**नालन्दा बिहार तथा हियूनसांग का स्मारक**

**1799. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नालन्दा बिहार तथा हियूनसांग स्मारक का संयुक्त रूप से विकास करने के

के बारे में उनके मंत्रालय द्वारा स्वीकार की गई योजना की मोटी-मोटी बातें क्या हैं और इस पर कितना व्यय होगा ;

(ख) यह योजना कब क्रियान्वित की जायेगी ; और

(ग) क्या इन बिहार की बौद्ध शिक्षा के अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिये अन्य देशों से भी सहयोग प्राप्त हो रहा है ।

**शिक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) :** (क) और (ख). तदर्थ समिति द्वारा सिफारिश की गई योजना में नव नालन्दा महाविहार तथा हयूनसांग स्मारक कक्ष को एक संयुक्त प्रबन्धक बोर्ड के अधीन, बौद्ध अध्ययन के अनुसन्धान तथा शिक्षा प्राप्ति के एक संयुक्त केन्द्र के रूप में समेकित विकास करने की व्यवस्था है, जो सोमायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अधीन एक रजिस्टर्ड स्वायत्त-शासी निकाय हो सकता है। समिति के अनुसार प्रथम पांच वर्षों में योजना पर 50.56 लाख रुपये अनावर्ती और 31.52 लाख रुपये आवर्ती खर्च होने का अनुमान है। योजना और खर्च के तड़मीने सरकार के विचाराधीन हैं। योजना के अनुमोदित होने और इस प्रयोजन के लिए धन उपलब्ध होने पर, योजना को कार्यान्वित करने के लिए हाथ में लिया जायेगा।

(ग) इस प्रायोजना में अन्य देशों के सहयोग के प्रश्न पर अभी तक विचार नहीं किया गया है।

**Safety rules in coal mines**

**1800. Shri S. M. Banerjee:** Will the Minister of Labour, Employment and Rehabilitation be pleased to state:

(a) whether it is a fact that safety rules are grossly violated by the coal mine owners resulting in serious accidents; and

(b) if so, the steps taken in the matter?

**The Deputy Minister in the Ministry of Labour, Employment and Beha-**

**bilitation (Shri Shah Nawaz Khan):**

(a) It will not be correct to say that Safety Rules are grossly violated. Violations do occur but there is greater safety consciousness now.

(b) Apart from inspection of mines, action under Section 22 of the Mines Act and prosecutions, more stress is being laid on Safety education and training. Safety weeks are now being organised in all mining areas. The National Council for Safety in Mines set up in 1963 is stepping up its activities. Mines Vocational Training Rules have been brought into force with effect from 1st August, 1966 in coal mining areas of West Bengal and Bihar. The progress in the matter of safety is also being reviewed from time to time at Mines Safety Conferences, the last of which was held at Calcutta on 9-10th July, 1966.

#### C.I.A. of U.S.A. in India

**1801. Shri P. C. Borooah:**

**Shri Sidheshwar Prasad:**

**Shri Rishang Keishing:**

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) whether Government have probed into the *modus operandi* of the Central Intelligence Agency of the U.S.A. in India and in relation to this country; and

(b) if so, the result thereof?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi):** (a) and (b). It will not be in the public interest to disclose the information.

**अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में खेती योग्य भूमि का विकास**

**1802. श्री हुकम चन्द कछवाय :**

**श्री रामेश्वरानन्द :**

**श्री रघुनाथ सिंह :**

क्या श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में खेती योग्य भूमि विक-

सित करने के लिए एक योजना तैयार की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब पूरा हो जायेगा ;

(ग) उक्त योजना पर कितना व्यय होने की सम्भावना है और इसके अन्तर्गत कुल कितने एकड़ भूमि में खेती होने लगेगी और उससे कितना अनाज पैदा होने की आशा है ; और

(घ) यह भूमि किन व्यक्तियों को दी जायेगी ?

**श्रम, रोजगार तथा पुनर्वसि उप-मंत्री (श्री बा० रा० चव्हाण) :** (क) से (ग). जी, हां । अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के समेकित विकास कार्यक्रम तैयार करने के लिये एक अन्तर्विभागीय टीम स्थापित की गई थी । टीम की रिपोर्ट संसद् की लाइब्रेरी में रख दी गई है ।

टीम ने यह सुझाव दिया है कि आगामी 10 से 15 वर्षों के बीच लगभग 1,25,000 एकड़ भूमि का सुधार किया जा सकता है । आगामी चार या पांच वर्षों के बीच 30,000 एकड़ भूमि के सुधार की प्रस्तावना है । मध्य अन्दमान (बीटापुर) में उपलब्ध 3,000 एकड़ भूमि को खेती योग्य बनाने का कार्य पिछले वर्ष चालू कर दिया गया था और चालू मौसम के अन्त तक लगभग 1,200 एकड़ भूमि का सुधार कर दिया गया था । जैसे अधिक से अधिक भूमि को खेती योग्य बनाया जाता है, भूमि सर्वेक्षण के आधार पर उसका सर्वोत्तम उपयोग किया जायेगा । ऐसे सर्वेक्षण संगठित किये जा रहे हैं । विशिष्ट द्वीप समूह से सम्बन्धित विशिष्ट भूमि को खेती योग्य बनाने की परियोजना के बारे में व्यौरा तैयार किया जा रहा है । वन के स्वरूप तथा जिस प्रयोजन के लिये भूमि को प्रयोग में लाया जायेगा उसके आधार पर एक द्वीप से दूसरे द्वीप में भूमि को खेती योग्य बनाने की लागत